

## वन आश्रितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं : रजनीश



**पलिया-खीरी (विधान केसरी)।** भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण किये लाकडाउन को यहां के वनविभाग द्वारा शोषण का हथियार बना लिया गया है। यहां बसे थारू जनजाति के गांवों में बसे थारू जनजाति के लोगों को लगातार झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और वनाधिकार कानून और

अपने पारम्परिक अधिकारों के तहत जलौनी लकड़ी व लघुवनोपज के एकत्रीकरण के लिये गयी महिलाओं को अपमानित करना और लोगों पर झूठे मुकदमें लादने सहित बड़ी रकम में अवैध तरीके से जुमाने वसूल करने की घटनायें लगातार अंजाम दी जा रही हैं। इसके अलावा ग्राम कजरिया में लोगों की शिकायत है कि उनके गांव के चारों तरफ

गृहमंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2020 को ही आदेश जारी करके अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वननिवासियों को लघुवनोपज के एकत्रीकरण की छूट प्रदान कर दी गयी थी। इन्हीं सब मुद्दों को उठाते हुए शनिवार को सुरमा से लेकर कजरिया तक तमाम गांवों की महिलाओं ने इकट्ठा होकर उपजिलाधिकारी पलियाअध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को एक ज्ञापन सौंपा। जिस पर उपजिलाधिकारी द्वारा 2 दिन बाद बातचीत करने का आश्वासन दिया है। इस ज्ञापन में थारू महिलाओं द्वारा चेतावनी भी दी गयी है कि अगर समय रहते वन विभाग की इन कारगुजारियों पर रोक नहीं लगी तो उन्हें मजबूर होकर जमीन पर उतर कर आंदोलन करना होगा। अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रजनीश ने कहा कि वन विभाग द्वारा की जा रही यह सभी कानून विरोधी कार्रवाईयां साबित करती हैं कि वे महामारी की आपदा से जूझ रहे आदिवासी वनाश्रितों को राहत देने के बजाय समुदायों के उत्पीड़न के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे समुदायों द्वारा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल अगर लोग मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो इसके लिये पूरी तरह से वन विभाग व प्रशासन जिम्मेदार होंगे।

### शोषण

महिलाओं को अपमानित करने और लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप

## थारू जनजाति के लोगों का उत्पीड़न कर रहा वन विभाग

अमृत विचार, पलियाकलां-खीरी।

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण किये लाकडाउन को वन विभाग द्वारा शोषण का हथियार बना लिया गया है। यहां बसे थारू जनजाति के गांवों में बसे थारू जनजाति के लोगों को लगातार झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और वनाधिकार कानून और अपने पारम्परिक अधिकारों के तहत जलौनी लकड़ी व लघु वनोपज के एकत्रीकरण के लिये गयी महिलाओं को अपमानित करना और लोगों पर झूठे मुकदमें लादने सहित बड़ी रकम में अवैध तरीके से जुमाने वसूल करने की घटनायें लगातार अंजाम दी जा रही हैं।

ग्राम कजरिया में लोगों की



वनविभाग द्वारा खोदी गई खाई।

शिकायत है कि उनके गांव के चारों तरफ 6 से 7 मीटर गहरी खाई खो दी गयी है। जिससे गांव के पानी की निकासी बाधित हो रही है और गांव के लोगों का अपने मवेशियों को जंगल में चराने के

लिये ले जाना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों से झूठ बोला जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण हुए लाकडाउन में उन्हें जंगल जाने की इजाजत नहीं है। जबकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2020 को ही आदेश जारी करके अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वननिवासियों को लघु वनोपज के एकत्रीकरण की छूट प्रदान कर दी गयी थी।

इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए सुरमा से लेकर कजरिया तक तमाम गांवों की महिलाओं ने इकट्ठा होकर उपजिलाधिकारी पलिया अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को एक ज्ञापन सौंपा। जिस पर उपजिलाधिकारी द्वारा 2 दिन बाद बातचीत करने का आश्वासन दिया है। इस ज्ञापन में थारू महिलाओं द्वारा चेतावनी भी दी गयी

है कि अगर समय रहते वन विभाग की इन कारगुजारियों पर रोक नहीं लगी तो उन्हें मजबूर होकर जमीन पर उतर कर आंदोलन करना होगा। वहीं अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रजनीश ने कहा कि वन विभाग द्वारा की जा रही यह सभी कानून विरोधी कार्रवाईयां साबित करती हैं कि वह महामारी की आपदा से जूझ रहे आदिवासी वनाश्रितों को राहत देने के बजाय समुदायों के उत्पीड़न के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे समुदायों द्वारा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल अगर लोग मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो इसके लिये पूरी तरह से वन विभाग व प्रशासन जिम्मेदार होंगे।

## थारु जन जाति की महिलाओं के साथ हुए अभद्रता के मामले में वन विभाग व पुलिस पर लिखा मुकदमा संगठित आदि वासी महिलाओं के दबाव में वन विभाग व पुलिस विभाग पर की गई कार्यवाही

पलिया कला खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व की बनकटी रेंज के कर्मचारियों ने आदि वासी जनजाति थारु ग्राम कजरिया में जमीनी विवाद के दौरान थारु संग की महिलाओं से कहा सुनी होते होते मारपीट शुरू हो गई गनीमत तो यह रही कि मौके पर ही तमाम सुरक्षा बल पहुंचकर मामले को शांत कराया आपको बता दें कि दुधवा की बनकटी रेंज के ग्राम कजरिया में जमीनी विवादित पर मामला इतना बिगड़ गया कि वन विभाग और थारु संघ की महिलाओं से झड़प शुरू होने लगी धीरे धीरे काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित होते हुए वन विभाग का विरोध करने लगी इसी बीच थारु क्षेत्र की तमाम महिलाओं ने दुधवा की बनकटी रेंज कजरिया को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया इसी बीच राघवेंद्र पुत्र रामाश्रय रमेश पुत्र सियाराम निवासी कजरिया तथा शिवेंद्र की मां को वन कर्मियों ने बंधक बना लिया पीड़ित थारु महिलाओं ने कहा दो लोगों को बंधक बनाया था उनमें एक महिला भी मौजूद थी जिसको बनकटी रेंज के वन कर्मियों ने युवक व महिलाओं को बंदूक की बट व लाठी डंडों से पीट पीटकर लहू लुहान कर दिया और महिला के कपड़े भी



फाड़ दिए वहीं तमाम आरोप लगाते हुए थारु जनजाति के संग महिलाओं ने इससे पूर्व भी हुए कई मामलों का खुलासा करते हुए वन विभाग को कोसा जिसमें अभी हाल ही में बनकटी रेंज में रेंजर के ऊपर 70

हजार रुपये लेने का आरोप लगा था जिसकी खबर अखबारों में छपने के बाद से डिप्टी डायरेक्टर मनोज सोनकर ने जांच के आदेश दे दिए थे इसी पर घबराए बनकटी रेंज के रेंजर साहब ने पीड़ित को 70 हजार रुपये वापस करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की रणनीति बनाने लगे या कहा जाए तो अपनी नौकरी बचाने के लिए पीड़ित को नोटिस भेज दी गयी वही मामला जब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो सभी विभागों के हाथ पांव फूल गए वहीं थारु संघ की महिलाओं ने एकत्रित होते हुए कार्रवाई की मांग की जिसमें वन विभाग द्वारा थारु आदि वासी महिला के साथ हुई बलात्कार की कोशिश व मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को सुबह संगठित आदि वासी महिलाओं के दबाव में थाना गौरीफंटा द्वारा तीन वन विभाग के अधिकारियों रेंजर बनकटी आलोक शर्मा उपरेंज अधिकारी सुनील शर्मा वन कर्मी नरेंद्र व गौरीफंटा चौकी के भट्ट को नामजद करते हुए आई पीसी 1860 की धारा 323 504 566, 154, 393, 376, 611, 364 और एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2अ) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है चोटिल महिलाओं को डाक्टरों जांच के लिए जिला अस्पताल लखीमपुर के लिए रवाना भी कर दिया गया है।

# 3 वन कर्मियों समेत एसआई पर मुकदमा

पलियाकलां-खीरी | हिसं

## कार्रवाई

कजरिया में जंगल के पास स्थित भूमि पर धान बोने से मना करने पर वन कर्मियों व थारू महिलाओं के विवाद में गौरीफंटा पुलिस ने तीन वन कर्मियों सहित एसआई पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वन कर्मियों में बनकटी रेंजर आलोक शर्मा, सुनील शर्मा, नरेंद्र के अलावा एसआई भट्ट को नामजद किया गया है। उधर वन विभाग की तहरीर पर नामजद 25 ग्रामीणों पर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिलाओं को जिला अस्पताल भेजा गया है।

बता दें कि थारू क्षेत्र के गांव कजरिया में जंगल के पास स्थित ग्रामीणों द्वारा काफी समय से जोती जा रही वन भूमि पर पहुंचे वन कर्मियों ने ग्रामीणों को धान की फसल बोने से इनकार कर दिया था। फसल बोने से इनकार करने के बाद ग्रामीणों का वन कर्मियों पर विवाद शुरू हो गया था। वन कर्मियों का आरोप

- 25 नामजद ग्रामीणों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा
- थारू महिलाओं और वन कर्मियों में मारपीट के बाद कार्रवाई

है कि महिलाओं ने अभद्रता की और उनका असलहा छीनकर मारपीट की। वहीं थारू महिलाओं का आरोप है कि वन विभाग ने उनके कपड़े फाड़े और हमारे साथ मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। थारू ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर फायरिंग का भी आरोप लगाया था। बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग कोतवाली पहुंचे थे। महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीन वन कर्मियों सहित गौरीफंटा में तैनात एक एसआई पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर वन विभाग से दी तहरीर पर नामजद 25 ग्रामीणों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।